(घ) चूंकि "पुलिस तथा लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं इसलिये महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों सहित, अपराधों को दर्ज करना, छानबीन करना, पता लगाना और अपराधों को रोकने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की है। तथापि, ऐसे अपराधों को रोकने के लिये भारत सरकार द्वारा कई उपाय शुरू किये गये हैं। दहेज निषेध अधिनियम (1961) को और अधिक कठोर बनाने के लिये 1984 तथा 1986 में संशोधित किया गया था। न केवल दहेज मौतों के मामलों बल्कि विवाहित महिलाओं के प्रति अत्याचार के मामलों से भी प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिये भारतीय दण्ड संहिता दण्ड प्रक्रिया संहिता (1973) तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम (1872) में संशोधन किया गया है। महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचारों से संबंधित कानूनों को प्रभावकारी ढंग से लागू करने के लिये राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को समय-समय पर निर्देश/दिशा निर्देश भी जारी किये गये हैं। इसके अलावा, महिलाओं को सकारात्मक रूप में पेश करने के लिये मीडीया का प्रयोग भी किया जा रहा है। जनता को जागरूक करने के लिये शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। महिलाओं के स्तर को सुधारने के लिये किये जा रहे अन्य प्रयासों में ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास कार्यक्रम (डी० डब्ल्यू० ए० सी० आर० ए०) तथा महिला साक्षरता कार्यक्रम जैसे कुछ कार्यक्रम हैं।

Activities of Militants in Indo-Nepal Border

4698. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Indo-Nepalese border has become a haven for Kashmiri militants;

(b) if so, the total number of militants who infiltrated into India and were apprehended;

(c) whether it is a fact that Government have approached the Government of Nepal if so, what is their response; and

(d) what steps Government propose to take to tackle the situation ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. M. SAYEED) : (a) Government are aware that Indo-Nepal border is exploited by the Kashmiri militants.

(b) 10 persons have been arrested during the period from June 1993 to February 1994.

(c) Yes, Sir. The Government of Nepal has cooperated in preventing illegal activities by Indian militants from their territory.

(d) We have sensitised the Government of Nepal on this issue. Attempts have been made for better cooperation and exchange of information with the Government of Nepal.

List of citizens, in Assam

4699. SHRI BHADRESWAR GOHAIN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) what is the progress made so far in preparing the list of citizens upto 1966 in Assam in accordance with the Assam Accord;

(b) whether the list has been completed uptil now; and

(c) if not, by when it will be completed ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJESH PILOT) : (a) to (c) In terms of a provision of Assam Accord all persons who came to Assam prior to 1-1-1966 including those amongst them whose names appeared in the electoral rolls used in 1967 elections were to be regularised as Indian Citizens. The Accord also provides for detection of foreigners who came